



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 1992/वैशाख 31, 1914

No. 94]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1992/VAISAKHA 31, 1914

इस भाग में भिन्न गूठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

विषय:— केलेण्डर वर्ष 1992-93 के लिए उन देशों को परिष्कारित तथा
निटियर के सम्बन्ध में ओ जी एल-3 के धर्तगत नियति संबंधी
मार्गदर्शी सिद्धांत जिन देशों में इस प्रकार के निर्यात को मात्रा-
प्रतिबंधों के सहित कर दिया जाता है।

स. 1/110/91-ई पी (टी एण्ड जे)-1 (अप्रैल):— उपरोक्त
विषय पर दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई पी
(टी एण्ड जे)-1 (अप्रैल) और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 1/99/90
ई पी (टी एण्ड जे) 1 (अप्रैल) दिनांक 7-8-91, इ 1/4/90-ई पी.
(टी एण्ड जे) 1 दिनांक 13-11-91 तथा 1/4/90-ई पी. (टी एण्ड जे)-
1 (अप्रैल) दिनांक 11-12-1991 की और ध्यान आकर्षित किया जाता
है। यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना
सं. 1/4/90-ई पी. (टी एण्ड जे) (अप्रैल) में निम्नोक्त अनुसार संशोधन
किया जाए:

2. पैरा 16 में एक नया उप-पैरा (iv) अ.इ दिया जाएगा जो इस
प्रकार पढ़ा जाए:

16 (iv) (क) उन निर्यातकों को जिनको आधार अवधि के दौरान
उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर संबंधित प्राबंजन
वर्ष के लिये 25,000 अक्षर में अधिकतम बिगत निष्पादन
हकदारी का प्राबंजन किया गया हो जिनमें सभी देशों/
श्रेणियों को निर्यात शामिल है ई एम डी/डी जी के स्थान
पर निम्नलिखित शर्तों पर वैध प्रावधान (एल यू टी)
देने का विकल्प होगा:-

(क) ई एम डी/डी जी के स्थान पर वैध प्रावधान
देने की सुविधा बिगत निष्पादन हकदारी, गैर-
कोटा हकदारी, द्विनिर्माण निर्यात हकदारी और
सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी योजनाओं के धर्तगत
प्राप्त निर्यातकों को हकदारियों के विस्तार/
पुनः वैधता में लागू होंगे। यह सुविधा
पढ़ने आओ, पढ़ने पाओ योजना में प्राबंटनों
या विस्तार के लिये उत्तम नहीं होंगे।
यह सुविधा गैर-कोटा हकदारी योजना अथवा
बिगत निष्पादन के अंतर्गत प्राप्त हकदारियों
के विस्तार/पुनः वैधता में भी लागू नहीं होंगे।

(ख) यदि वैध प्रावधान में शामिल की गई हकदारियों
के सम्बन्ध में ज्ञान की गई किसी धर्तराशि के

